SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam...

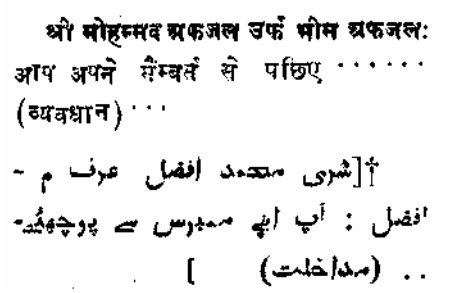

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will discuss Ihe Budget (General), 1991-92... *(tnterruptions)...* That matter is over... *(Interruptions)..* . What do you want to say, Mr. Jacob?... *(Interruptions).* . . Order, please.

SHRI M. M. JACOB: Madam, regarding the Budget one request have to make. Yesterday, we had consultations with the Party leaders who were present in the Chamber and this morning I have also met some leaders in this connection. The Vote on Account was passed in the Lok Sabha without debate and aftsrwards they continued with the consideration of the Budget. So I suggest, if most of the Members agree to, to have ihe voting first and then the debate.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Agreed?

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Madam, let them discuss the Vote on Account first and then we will discuss the Budget.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Madam, we agree to it if they are serious into the investigation of Rajiv Gandhi's assassination.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whethei you pass the Vote on Account or you don't pass the Vote on Account, everybody is serious about Rajiv Gandhi. Before I call the names of Members to speak... *(Interruptions)...* Now will take up the Appropriation (Vote on Account} No. 2 Bill, 1991. Dr. Manmohan Singh...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I would like to make one submission.

fTranstiteration in Arabic Script.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You gave your commitment and now you want to make your submission. How is it possible? It is not a conditional commit-, ment...

SHRI S. JAIPAL REDDY: No, no, no. We are only keen to have a commitment from the Government that this will not be treated as a precedent.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I can assure you that is not going to be made a precedent. I assure you from the Chair. .. *.(Interruptions)..* , I can assure you from the Chair.. . *(Interruptions)...* I know what he Hays. I can ready your mind also...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam Deputy Chairperson, you must permit us to make our submissions. We want an assurance from the Government that this will never be treated as a precedent,

THE DEPUTY CHAIRMAN: O.K. Given. The Minister can also give that.

THE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT NO. 2 BILL, 1991

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Madam, I beg to move:

"That the Bill to provide for tha withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a.part of the financial year 1991-92, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration".

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Wo shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 to 4 *and the Schedule were vided to the Bill, Clause I, the Enactir. Yormula and the Title were added to the Bill.*

SHRI MANMOHAN SINGH: Madam, I beg to move:

"That the Bill be returned".

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we go to the Budget. Shri Vishvjit Singh (*Interruptions*) ...

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया,

उपसभापति: अभी तो बजट हो रहा है, अभी बजट हो जायेगा.... (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव: महोदया बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): मैडम एक मिनट।

उपसभापति: अभी बजट डिस्कश हो जाने दीजिये।

श्री राम नरेश यादव: पीठ की तरफ से मुझे आश्वासन मिला था कि मैं बाद में आपको मौका दे दूंगी। इसीलिये मैडम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार सूखे से बहुत तबाह हो रहे है। इतनी तबाही है कि सारे खेत न और सारे लोग परेशान हैं। न प्रदेश सरकार का ध्यान उधर है और न केन्द्र सरकार का ध्यान है। ऐसी स्थिति में जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया है। खेतों में जो बीज डाला गया है वह सारे के सारे स्वाहा हो गये हैं, पानी पड़ नहीं रहा है, ऐसी स्थिति है। इस दिशा में सरकार को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिये और विचार ही नहीं करना चाहिये बल्कि सरकार को चाहिये कि वह एक बयान के साथ आये सदन के सामने और बताये कि पूरे देश के अंदर किन-किन राज्यों में सूखा है और सूखे से निबटने के लिये सरकार की तरफ से क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार को क्या-क्या निर्देश देने जा रही हैं? अतः माननीय मंत्री जी सदन के सामने एक वक्तव्य दें और जल्दी से जल्दी प्रदेश सरकारों को निर्देश दें ताकि उत्तर प्रदेश में जो समस्या पैदा हुई है .... (**व्यवधान**)

उपसभापति: मंत्री जी तो यहां फाइनेंस के हैं।

श्री राम नरेश यादव: और बिहार में जो समस्या पैदा हुई है उस समस्या का निराकरण बहुत हद तक हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर चाहता हूं कि इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये ताकि जो लोग संकट में पड़े हुये हैं वह संकट में न पड़ने पायें और वे राहत की सांस ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ, महोदया.... (**व्यवधान**)

उपसभापति: वह पूछ रहे हैं कि कौलिंग अटेंशन दिया है।

श्री राम नरेश यादव: कौलिंग अटेंशन दिया है।

उपसभापति: आपने दिया है तो चेयरमेन साहब कंसीडर करेंगे। समय होगा तो जरूर इस पर चर्चा होगी, सीरियस मामला है।

श्रीमती सत्या बहिन: मैडम, इस पर चर्चा होनी चाहिये। पूरा उत्तर भारत सूखे से परेशान हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कोई चिंता नहीं है कि किसानों को क्या मुसीबतें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है, इसको कोई परवाह, नहीं है उनको, वे केवल राजनीति में उलझे हुये हैं और अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिये अभी सांप्रदायिक दंगे करते हैं तो अभी गृह युद्ध उनको किसानों की सुविधाओं से कोई लेना-देना नहीं है। महोदय, इस पर एक वक्तव्य आना चाहिये कि राहत देने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार से न तो कोई उम्मीद है, न कुछ कर सकती है, न उनमें कोई क्षमता है, न ही उत्तर प्रदेश सरकार और न ही बिहार सरकार से... (**व्यवधान**)

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) .. (**व्यवधान**) उत्तर प्रदेश सरकार की बात यहां मत कीजिये, यह केन्द्र की बात है। उत्तर प्रदेश की बात उत्तर प्रदेश विधान सभा में कीजिये।

श्री राम नरेश यादव: यह उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है, सूखे पर किस तरह से राहत पहुंचे वह प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है।

श्री अश्विनी कुमार: यहां हमने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे दी है, जो आपने कट ली है, आपको पता नहीं है।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, we have to discuss drought problem whenever it occurs. Even if it occurs in U.P., we are entitled to discuss it.

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): अभी-अभी जो हारकर आये हैं उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिये।

उपसभापति: जो सूखे की बात है वह तो सीरियस लेना चाहिये।

श्री प्रमोद महाजन: उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जो कह रहे हैं, उसके बारे में ...(**व्यवधान**),

उपसभापति: प्लीज, आर्डर। उत्तर प्रदेश सरकार को सीरियसली लें या न लें जो सूखा पड़ा है देश में चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे कहीं भी हो वह बहुत गंभीर मामला है और सरकार को उसके बारे में कुछ न कुछ ध्यान देना चाहिये, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। बोलिये विश्वजित जी।

डा. अबरार अहमद (राजस्थान): धन्यवाद मैडम, आपने राजस्थान सरकार का नाम लिया।

THE BUDGET (GENERAL), 1991-92' — Condt.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): Madam Deputy-Chairman, I rise to support this Budget but my support is tempered with certain reservations. I know that this Budget document is actually a result of an earlier document which was circulated to the Members. I have expressed my apprehensions at that juncture when I said that the circulation of this document is actually a circulation of the entire economic policy of the Government of India. That joint policy statemen! actually carried within it details oi the entire economic package as desired by the Government, including the budget, the industrial policy, the trade policy and what I would refer to as the exist policy also. All of it i is there in that document. There is not one part of it referring to the budget which has been contravened and set in front of us. So our apprehensions were quite clear that that, in fact, was the document on which everything was based. One problem I find is that though this strategy has been spelt out as to what we are going to do—devaluation, seeking of IMF loan, disinvestment in the public sector—there is no clear thinking about what we want to achieve, what the results are that we want to achieve at the end of the term. We are making such systemic changes. What is going to happen at the end of the road? Merely talking in platitudes is not going to suffice. Merely saying that India has a glorious future, that we are going to take up a place in the world—all very well. How are you going to take a place in the world? Today our share of international trade has diminished to a miniscule percentage. What percentage of world trade do you eventually want to have for India at the end of your Plan? What are you planning? What is your time-bound programme for the public sector? How much percentage of the public sector shareholding are you going to finally disinvest? I know you said 20 percent in certain areas and then you talked about sick areas of the public